



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत की जीडीपी मापन प्रणाली को पुनः
निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है?

भारत की जीडीपी मापन प्रणाली को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है?

संदर्भ

- हाल ही में अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक संस्थानों के बीच हुई परिचर्चाओं ने चिंता व्यक्त की है कि भारत का वर्तमान जीडीपी मापन ढाँचा तीव्रता से बदलती, डिजिटल, अनौपचारिक और सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता।
- इसलिए, भारत 2026 में नई जीडीपी श्रृंखला का बेस इंयर संशोधन लागू करने जा रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष बनाया जाएगा।

जीडीपी क्या है और इसे कैसे मापा जाता है?

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है।
- भारत में प्रयुक्त विधियाँ:
 - उत्पादन (मूल्य वर्धित) विधि
 - आय विधि
 - व्यय विधि
- भारत मुख्यतः उत्पादन दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जिसमें कॉर्पोरेट और प्रशासनिक डेटाबेस का उपयोग होता है।
- भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जीडीपी डेटा संग्रह का प्रबंधन करता है।
- क्षेत्रों का योगदान:** भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, जो 61.5% है।
 - इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र (23%) और फिर कृषि क्षेत्र (15.4%) का योगदान है।

आधार वर्ष क्या है?

- आधार वर्ष एक मानक वर्ष होता है जिसका उपयोग आर्थिक और सांख्यिकीय गणनाओं में तुलना के लिए किया जाता है।
- यह एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है जिसके आधार पर जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी जैसे संकेतकों के वर्तमान मूल्यों को समय के साथ वास्तविक परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए मापा जाता है।
- महत्व:**
 - यह हमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर वास्तविक वृद्धि देखने की अनुमति देता है।
 - सूचकांक संख्याएँ बनाने में सहायता करता है (जैसे आधार वर्ष में CPI = 100)।
 - सुनिश्चित करता है कि डेटा अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, उपभोग पैटर्न और कीमतों को दर्शाए।

भारत की जीडीपी मापन प्रणाली को रीसेट करने की आवश्यकता क्यों है?

- पुराना आधार वर्ष (2011-12):** डिजिटलीकरण, सेवाओं के उदय और गिग इकॉनमी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जीडीपी अभी भी पुराने आधार वर्ष का उपयोग करती है, जिससे क्षेत्रीय भार विकृत होते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रथा प्रत्येक 5 वर्ष में आधार वर्ष संशोधित करने की सलाह देती है।

- अनौपचारिक क्षेत्र का कमजोर आकलन:** भारत के लगभग आधे कार्यबल के अनौपचारिक क्षेत्र में होने के बावजूद पुराने सर्वेक्षणों और अनुमानित मान्यताओं पर निर्भरता गलत आकलन की ओर ले जाती है, विशेषकर जीएसटी एवं कोविड व्यवधानों के बाद।
- MCA-21 डेटा पर अत्यधिक निर्भरता:** जीडीपी अनुमान कॉर्पोरेट फाइलिंग पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो सूक्ष्म उद्यमों और अनौपचारिक फर्मों को बाहर रखते हैं तथा निष्क्रिय या शेल कंपनियों को शामिल करते हैं, जिससे डेटा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- सेवाओं का कमजोर मापन:** सेवाएँ जीडीपी में लगभग 55% योगदान करती हैं, फिर भी स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल कार्य और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों का पर्याप्त मापन नहीं होता, साथ ही अमूर्त एवं गुणवत्ता सुधार भी उपेक्षित रहते हैं।
- रोजगार-विकास असंगति:** उच्च जीडीपी वृद्धि अनुपातिक रोजगार सृजन में परिवर्तित नहीं हुई है, जो दर्शाता है कि जीडीपी आँकड़े समावेशी या रोजगार-प्रधान वृद्धि को नहीं दर्शाते।
- कोविड के बाद संरचनात्मक बदलावों की अनदेखी:** छोटे उद्यमों का बंद होना और गिंग व प्लेटफॉर्म कार्य का विस्तार पूरी तरह परिलक्षित नहीं है, क्योंकि पद्धति अभी भी महामारी-पूर्व आर्थिक संरचना मानती है।
- वैकल्पिक डेटा का सीमित उपयोग:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के विपरीत, जो उपग्रह चित्र, बिजली उपयोग और डिजिटल लेन-देन डेटा का उपयोग करती हैं, भारत की जीडीपी गणना सर्वेक्षण-प्रधान एवं विलंबित बनी हुई है।

2026 का आधार वर्ष संशोधन एक अवसर के रूप में

- कमोडिटी-फलो दृष्टिकोण से बदलाव:** यह अधिकांश वस्तुओं में उपभोग का अनुमान लगाने के लिए कमोडिटी-फलो विधि से हट जाएगा।
- पहले ढाँचे में, 2011–12 अध्ययन से प्राप्त स्थिर अनुपातों का उपयोग वस्तुओं को मध्यवर्ती उपभोग, अंतिम उपभोग और अन्य उपयोगों के बीच आवंटित करने के लिए किया जाता था।
- संशोधित प्रणाली इसके बजाय गतिशील दरों और अनुपातों का उपयोग करेगी, जिससे अनुमान समय के साथ उपभोग पैटर्न बदलने पर विकसित हो सकें।
- ‘असंगतियों’ का उन्मूलन:** MoSPI वार्षिक जीडीपी संकलन में सीधे सप्लाई और यूज़ टेबल्स (SUTs) को एकीकृत करने की योजना बना रहा है।
- सप्लाई और यूज़ टेबल्स दिखाती हैं कि विभिन्न वस्तुएँ और सेवाएँ घरेलू उद्योगों एवं आयात द्वारा कैसे आपूर्ति की जाती हैं तथा वे विभिन्न मध्यवर्ती या अंतिम उपयोगों, जिसमें निर्यात भी शामिल है, के बीच कैसे वितरित होती हैं।
- यह दृष्टिकोण प्रारंभिक अनुमानों में असंगतियों को सीमित करने और अंतिम अनुमानों में उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- डिजिटल और प्रशासनिक डेटा का उपयोग:** निम्नलिखित डेटासेट्स पर बढ़ी हुई निर्भरता:
 - ई-वाहन (वाहन पंजीकरण)।
 - जीएसटी और अन्य प्रशासनिक अभिलेख।
- अपडेटेड सर्वेक्षण डेटा की रीढ़:** नई श्रृंखला में योगदान देने वाले प्रमुख सर्वेक्षणों में शामिल हैं:
 - घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022–23 और 2023–24।
 - औपचारिक और अनौपचारिक उद्यमों के अद्यतन सर्वेक्षण।

- ये पहले के मानकों की तुलना में उपभोग व्यवहार और उत्पादन गतिविधि पर अधिक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करने की संभावना हैं।

निष्कर्ष

- जीडीपी एक महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतक बना हुआ है, लेकिन पद्धतिगत अद्यतनों के बिना यह भारत के संरचनात्मक परिवर्तन को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का जोखिम उठाता है।
- रीसेट आवश्यक है ताकि जीडीपी साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, समावेशी विकास और सतत विकास के लिए एक अधिक विश्वसनीय उपकरण बन सके।

Source: LM

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी के आधार वर्ष और पद्धति का संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? इसके नीति-निर्माण और संघीय वित्त पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

